जागृति

वर्ष:62 अंक-4 मुम्बई मार्च 2018

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा
मधुबनी पेंटिंग्स को ई-मार्केट से जोड़ने का आश्वासन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 62 अंक-4 मुंबई मार्च 2018

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खलको

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719463
ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार ..... 3 से 31

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा मधुबनी पेंटिंग्स.....
एमएसएमई मंत्री द्वारा केन्द्रीय मधुमक्खीपालन अनुसन्धान.....
सिल्वर स्क्रीन पर अब खादी का जलवा:कंगना इसे "मणिकर्णिका".....
आयोग के मण्डलीय कार्यालय का हुब्बली में उद्घाटन.....
तिरुवनंतपुरम: "परिणामा"-खादी फैशन शो.....
अपनी खादी, अपना बाज़ार में.....
भारतीय रिटेलर्स संघ द्वारा आयोजित रिटेलर्स लीडरशिप शिखर.....
संयुक्त सचिव द्वारा बैंकरों के साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन.....
कर्नाटक में 91वर्ष पुरानी हेरिटेज वंदनावलु खादी संस्था का.....
आयोग मुख्यालय, मुंबई में खादी सुधार विकास कार्यक्रम पर.....
वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी उत्सव-2018.....
राजकोट में कारीगर सम्मेलन.....
त्रिवेंद्रम में पीपुल्स एजुकेशन कार्यक्रम.....
खादी भवन, मैसूर का उद्घाटन.....
सदस्य(उत्तरी क्षेत्र) द्वारा प्र.मं.रो.सृ. कार्यक्रम की समीक्षा.....
जम्मू में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक.....
घरेलू और निर्यात पर विपणन कार्यशाला.....
कश्मीर में दक्षता विकास प्रशिक्षण.....
1000 मधुमक्खी बक्से एवं अन्य उपकरणों का वितरण.....
कोल्हापुर में कुम्हारी प्रशिक्षण कार्यशाला.....
धोरडी, गुजरात में गांधी मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन.....
पी.एम.ई.जी.पी. योजना को धन्यवाद: समाज की मुख्यधारा.....
आरसेटी के राज्य निदेशकों और बैंकरों की समीक्षा.....
एमएसएमई मंत्रालय के लिए आम बजट के प्रावधान की मुख्य बातें.....
पीएनबी आरसेटी, रावरी द्वारा पीएमईजीपी के तहत एक उद्यमिता.....
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन.....
राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में पश्चिमी क्षेत्र की समीक्षा बैठक.....

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : विशेष ..... 32 से 37

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ ..... 38 से 43

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री द्वारा मधुबनी पेंटिंग्स को ई-मार्केट से जोड़ने का आश्वासन

अगर हम मधुबनी पेंटिंग्स, खादी और मखाना उद्योग को वाणिज्यिक आधार पर प्रोत्साहित करते हैं, तो यह लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है- यह बात केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कही।

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 14 फरवरी, 2016 को रांची में मधुबनी पेंटिंग्स स्फूर्ति क्लस्टर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी पेंटिंग्स को इस क्षेत्र का गौरव माना जाता है; इसलिए जल्द ही इस जिले में दो और क्लस्टरों को शुरू किया जाएगा और मधुबनी पेंटिंग्स हेतु बाजार बनाने के लिए शीघ्र ही इसे ई-मार्केटिंग के साथ जोड़ा जायेगा। इसके लिए कार्यप्रणाली पहले ही शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द हम इन प्रयासों की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करेंगे।

नवादा में याद किये गए कार्य

इस अवसर पर बोलते हुए एमएसएमई मंत्री ने नवादा में किए गए कार्य को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जब क्लस्टर खोला गया था, वहाँ केवल 700 कारीगर थे, एक साल के भीतर यह संख्या 1500 तक यानि दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा, हम इसे 20,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार और सशक्तिकरण के लिए करीब 600 महिलाएं इस क्लस्टर में जोड़ी जाएंगी।

इस अवसर पर सांसद झांझरवाड़ श्री वीरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र की हर महिला एक कलाकार है। उन्हें बस बुनियादी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया।

विधायक श्री रामपत पासवान ने कहा कि इस क्लस्टर से महिलाओं को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

स्थानीय विधायक समीर कुमार सेठ ने कारीगरों की दयनीय स्थिति के सुधार पर ज़ोर दिया।

मंत्री महोदय ने खादी संस्थाओं के सक्रिय रूप से कम प्रदर्शन करने और अच्छे परिणाम न देने के बारे में अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने कहा, उत्पादन में अधिक से अधिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी यार्न क्लस्टर के बहुत जल्द शुरू पर प्रकाश डाला।

एमएसएमई मंत्री द्वारा केन्द्रीय मधुमक्खीपालन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे का दौरा

पुणे, 3 फरवरी, 2018: केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 3 फरवरी, 2018 को खादी ग्रामोद्योग आयोग के गणेश खिंड रोड, पुणे स्थित केन्द्रीय मधुमक्खीपालन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया।

इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत संचालित की जा रही मधुमक्खीपालन गतिविधियों और इस क्षेत्र में रोज़गार के व्यापक अवसरों के बारे में बात की और वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताओं पर भी अपनी राय दी, उन्होंने कहा कि 2018-19 के बजट में रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर को भी विशेष महत्व दिया गया है।

आगे उन्होंने कहा कि बजट में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ा महत्व दिया गया है। 2017-18 के बजटीय आवंटन में 6481.96 करोड़ से 2018-19 में 6,552.61 करोड़ रुपए तक बढ़ा है। विभिन्न योजना शीर्षों में आवंटन 2017-18 में 3680 करोड रुपये से बढ़ाकर 2018-19 में 5852.61 करोड़ अर्थात 59 प्रतिशत की वृद्धि (सीजीटीएमएसई को छोड़कर) की गयी है।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी) के लिए आवंटन 2017-18 में 506 करोड रूपये से बढ़ाकर 2018-19 में 1006 करोड़ कर दिया है।

(शेष पृष्ठ 17 पर...)

सिल्वर स्क्रीन पर अब खादी का जलवा: कंगना इसे "मणिकर्णिका" में पहनेंगी

रूप में अपनी प्रमुख भूमिका सिल्वर स्क्रीन पर अदा कर रही है, वह इस आगामी महाकाव्य जीवनी फिल्म में देश की परंपरागत वस्त्र 'खादी' का प्रदर्शन करेंगी और भारत के इस सांस्कृतिक वस्त्र (खादी) को बढ़ावा देने के लिए -खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की पोशाक को प्रायोजित किया जा रहा है।

"उन्होंने आगे कहा," केवीआईसी के लिए आक्रमक विपणन और प्रमोशन रणनीति के संदर्भ

नई दिल्ली: कई सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा खादी वस्त्र अपनाने के पश्चात् , खादी अब सिल्वर स्क्रीन पर अपना रास्ता बना रही है ! सिने अभिनेत्री कंगना राणावत, 'मणिकर्णिका: फिल्म में 'झांसी की रानी' के

में यह एक मनोबल बूस्टर है कि वह (कंगना राणावत के रूप में रानी लक्ष्मीबाई) इस फिल्म में चरखे पर कताई करेंगे। इससे यह एक बार फिर साबित होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन से पहले, खादी हमारे देश में विकास कर रही थी और बाद में यही चरखा - जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।"

भारत की आजादी की भावना के नवीकरण में भाग लेने के लिए गर्व और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि चूंकि राणी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में जो कुछ किया था, उसके संदर्भ में वह सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक है। "उन्होंने आगे कहा," कि खादी लम्बे समय से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज से जुड़ी रही है। हम सभी जानते हैं कि 1926 में, गांधीजी ने 'खादी को स्वराज का प्रतीक' माना और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के इस वस्त्र के अंतिम सूत की कताई की। लेकिन, शायद कुछ लोगों को ही पता है कि गांधीजी का चरखा, सात दशक पूर्व मणिकर्णिका या मनु के रूप में वाराणसी में जन्मी 'एक लड़की' ने केवल वेदों और पुराणों तथा घुड़ सवारी और युद्ध में ही महारत हासिल नहीं की बल्कि उसने झांसी की रानी होने से पूर्व कताई तथा बुनाई भी सीख ली थी। यह, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए आक्रमक विपणन और प्रमोशन रणनीति के संदर्भ में एक मनोबल बूस्टर है कि एक अभिनेत्री रानी लक्ष्मीबाई के रूप में इस फिल्म में चरखे पर कताई करते हुए दिखेगी।

यह उल्लेखनीय है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा प्रायोजित, फिल्म की पोशाक डिजाइनर नीता लुल्ला द्वारा डिजाइन की जाएगी, नीता लुल्ला ने केवीआईसी से लगभग 26 लाख रुपये की लागत वाले खादी वस्त्र लिए हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना के अनुसार, फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वस्त्रों में रेशम, कपास, मलमल और कुछ ऊन के मिश्रण से तैयार की गयी पोशाकें भी शामिल हैं।

इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली कंगना को इस फिल्म में चरखा का उपयोग करते हुए भी दिखाया जाएगा, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।

इस फिल्म परियोजना के लिए खादी वस्त्र का उपयोग करने के बारे में डिजाईनर नीता लुल्ला उत्साहित हैं, उन्होंने बताया, खादी वस्त्र से प्रभावित पहले से ही वह अपनी निजी जिंदगी रही हैं और अब वह सिल्वर स्क्रीन पर भी इस देशी वस्त्र का इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि खादी बहुत से चरित्रों का एक प्रतीक है। मैं विश्व स्तर पर एक विशेष संग्रह लॉन्च करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ पहले से ही बातचीत कर रही हूं, जोकि इस पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र को मिलेनियल पीढ़ी के साथ प्रतिरूप करने एवं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिक्री केन्द्रों के स्वरुप में एक व्यापक बदलाव लाएगा। उन्होंने आगे कहा कि "एक डिजाइनर के रूप में खादी- स्थिरता, छाया-चित्रण, मजबूत डिजाइन विस्तार और एक अत्याधुनिक सौंदर्य सहित मेरे लिए यह सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है", डिजाइनर नीता लूला ने कहा कि,"जो खादी पर्दे मुझे आकर्षित करते हैं उसे उपयोग में लाती हूँ, यह आरामदायक और अभी तक शानदार हैं, और पहनने वाला इस वस्त्र में सबसे अधिक आराम महसूस करता है।"

दूसरी तरफ, फिल्म निर्माता कमल जैन ने कहा कि पूरे यूनिट को केवीआईसी के सहयोग करने पर गर्व है और खादी की सबसे बेहतर रेंज प्रदान करने में उनके योगदान की सराहना की जोकि फिल्म में पहले से ही खादी की वेशभूषा के लिए काफी रूचि बढ़ गयी थी। उन्होंने आगे कहा, "फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही है और भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने में ये अनोखी वेशभूषा- एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"

30 साल की मांग के बाद

आयोग के मण्डलीय कार्यालय का हुब्बली में उद्घाटन

खादी कारीगर सम्मेलन में 6,000 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया

हुब्बली (कर्नाटक) : प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खादी के प्रति लगाव का राष्ट्रव्यापी प्रभाव दिखाई देता है! और जिसका प्रभाव अब कर्नाटक में भी दिखायी दे रहा है, जहां हुब्बली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का एक डिवीजनल कार्यालय खोलने की मांग पिछले 30 साल से लंबित थी – अंततः शनिवार को यह मांग पूरी हो गई, जब पेयजल और जल निकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रमेश चंदप्पा जिगजिनीगी ने हुब्बली के बेंगीरी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, इसके बाद राज्य भर से आये 6,000 से अधिक खादी कारीगरों के एक भव्य 'खादी कारीगर सम्मेलन' का उद्घाटन किया गया।

अपने उद्घाटन संबोधन में माननीयमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में खादी संस्थाओं के लिए 32.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । खादी और

ग्रामोद्योग आयोग को 100 प्रतिशत अनुदान जारी करने के लिए सरकार से कहा है। उन्होंने कहा, "यह कर्नाटक के बुनकरों और कत्तिनों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इस राज्य ने 135 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों का उत्पादन किया गया है और उनमें से 109 करोड़ रुपए के उत्पादों की बिक्री की गई है।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नए डिवीजनल कार्यालय के उद्घाटन से संस्थागत प्रतिनिधियों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा। यह अपने तरह का एक भव्य कार्यक्रम है, जब 6,000 से अधिक विशाल जनसमूह एक छत के नीचे एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह नया मंडलीय कार्यालय, बगलकोट, बेलागवी, बेल्लारी, बिदर, बिजयपुरा, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी, हावेरी, कोप्पल, रायचूर, उत्तर कन्नड़ और यदागिरी आदि ज़िलों के पूरे क्षेत्र में खादी गतिविधियों का विकास करेगा। यह "नया डिवीजनल कार्यालय के तहत 31 सीधे सहायता प्राप्त संस्थाएं, 48 राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत्त हैं और खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। यह कार्यालय, ऐसी संस्थाओं की देखरेख करेगा तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, इस क्षेत्र के कारीगरों को और अधिक अर्जन करने का मौका भी देगा।"

श्री सक्सेना ने आगे कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने के लिए केवल कर्नाटक का कपास खादी अधिकृत है, उन्होंने कहा कि केवल कर्नाटक खादी बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर सकता है। "राष्ट्रीय ध्वज के लिए बीआईएस द्वाराआईएस-1(1968) संख्या आवंटित की गयी है और जिसके अनुसार उसका मापन, सूत का काउंट, रंग, रंग की स्थिरता और प्रति इंच टांके की संख्या आदि का मानकीकरण सीमित है। "उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक खादी हमारे तिरंगे का पर्याय बन गया है।"

इस भव्य खादी कारीगर सम्मेलन में 50 से 94 वर्ष तक के कुशल बुनकर और कत्तिनों को भी सम्मानित किया गया। कर्नाटक के विपक्ष के नेता श्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि राज्य में कपास की फसल बेहतर गुणवत्ता की है।

इस सम्मेलन में भाग लेने और संबोधित करने वाले अन्य मान्यवरों में धारवाड़ के सांसद श्री प्रहलाद वी. जोशी, हुब्बली के मेयर श्री डी.के. चव्हाण, कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री यलुवहल्ली एन. रमेश, केकेजीएसएस (फेडरेशन) के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉ. पाटिल पट्टण्णा और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा इत्यादि शामिल थे।

तिरुवनंतपुरम में 'परिणामा' खादी फैशन शो

तिरुवनंतपुरम: "परिणामा-प्रासंगिक रहने के लिए बदलाव", 23 फरवरी, 2018 को ओलंपिया हॉल, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम में एक खादी फैशन शो आयोजित किया गया, जैसाकि शीर्षक से पता चलता है। खादी को बढ़ावा देने के लिए यह खादी फैशन शो-खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और केरल सर्वोदय संघ एवं एलबीएस महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था।

यह फैशन शो, भाग्यमाला ऑडिटोरियम, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम में आयोजित "खादी एक्सपो-2018" का एक हिस्सा था, जिसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम की उप-कलेक्टर, आईएएस, श्रीमती दिव्या एस. अय्यर द्वारा किया गया।

"इस एक्सपो का उद्देश्य- खादी वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा देना तथा कारीगर को बिक्री के जरिए उन्हें बेहतर उपार्जन करने में मदद करना है।

इस अपसर पर आयोग की राज्य निदेशक, केरल

श्रीमती के. पी. लालिथामणि ने कहा, "हम फैशन शो के माध्यम से युवा पीढ़ी को लक्षित कर रहे हैं। इस एक्सपो में सभी उत्पादों पर 30% तक की छूट दी जा रही है।"

इस प्रदर्शनी में लगभग खादी के 75 स्टाल और ग्रामोद्योग के विभिन्न 40 स्टाल लगाये गए थे। एक्सपो में सूती खादी, सिल्क खादी, मलमल खादी सामग्री, जामदानी सिल्क, बाटिक सिल्क, कढ़ाई सिल्क, बालूचेरी सिल्क, जूट सिल्क, जूट सिल्क साड़ी, बिस्तर, गद्दे, तकिए, और कोलापुरी जूते, लेदर बैग्स, चर्म के उत्पाद के अलावा दूसरे राज्यों के बांस के फर्नीचर और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के साथ खादी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

अपनी खादी, अपना बाज़ार में

मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर खादी की उपलब्धता को सुगम लिए मुंबई के उपनगरों चारकोप और मुलुंड में खादी कॉर्नर खोलने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग खुदरा क्षेत्र में एक नया आयाम बनाने करने के लिए पुनः तैयार है।

मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर खादी की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए मुंबई के उपनगरों चारकोप और मुलुंड में खादी कॉर्नर खोलने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग खुदरा क्षेत्र में एक नया आयाम बनाने करने के लिए पुनः तैयार है, जो खादी की बिक्री बढ़ाने 'शॉप-इन-शॉप' के निर्माण में यह दूसरा प्रमुख समझौता है। खादी के विभिन्न उत्पादों को बेचने के लिए 'अपना बाज़ार' के चारकोप स्टोर से शुरू होने वाले खादी कॉर्नर के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विपणन निदेशक श्री आई. जवाहर एवं अपना बाज़ार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस टी काजले ने केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना तथा अपना बाज़ार के अध्यक्ष श्री अनिल गन्गर की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये। इससे पूर्व ग्लोबस द्वारा ग्रेटर इंडिया प्लेस मॉल, नोएडा और अहमदाबाद में 'खादी-शॉप - इन-शॉप' खोला गया है।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा, " खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी को जन-जन की पहुँच तक लाने के लिए सभी संभव तरीकों की तलाश कर रहा है। हमारी यह नयी सोच प्रमुख खुदरा शोरूमों जैसे शॉपर्स स्टॉप, स्टार बाजार, इन्फ़िनिटी मॉल, पेंटालून, बिग बाजार या डी-मार्ट बाजार, पैंटालूंस इत्यादि में खादी कॉर्नर शुरू करना है। गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना हम उत्पादों को प्रभावी व प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हम हमारे उत्पादों को बढ़ावा देते हैं जिसका अर्थ है कि हम कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धी हैं।"

खादी और खादी उत्पादों के निर्यात पर उन्होंने कहा कि 1 लाख मीटर की खादी डेनिम जीन्स बनाने के लिए अरविंद मिल्स हमारे द्वारा सालाना खरीद रही है जिसे वे विदेशी कंपनियों को भी निर्यात करते हैं|

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि भारत में लगभग

400 गांवों को खादी गाँव के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसका चुनाव योजना आयोग द्वारा किया गया है तथा यह प्रक्रिया अगस्त 2018 तक पूरी होने की संभावना है। इन गांवों के कारीगरों का प्राथमिक व्यवसाय खादी बनाने का होगा।

भारत में खुदरा उद्योग के विकास के लिए सही माहौल बनाने के लिए अंततः मूल्यों को फिर से परिभाषित किया जाएगा, आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी हमारे परंपरागत कारीगरों की संस्कृति, नैतिकता और कौशल को दर्शाती है। यह समझौता खादी को न केवल सभी के लिए उपलब्ध कराएगा बल्कि इसके कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि से कारीगरों की आय में भी वृद्धि होगी।

विगत दो वर्षों में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा खादी को बढ़ावा देने से इसमें 34% वृद्धि हुई है, जोकि उल्लेखनीय है। लेकिन इसे दूसरे स्तर तक ले जाने के लिए और राष्ट्र के हर कोने में उपलब्ध करना हमारा उद्देश्य है।

अपना बाजार स्टोरों के साथ करार करने के संबंध में जानकारी देते हुए अपना बाज़ार के अध्यक्ष श्री अनिल गन्गर ने कहा कि खादी की अवधारणा मुंबई में दो चरणों से शुरू होगी। उन्होंने कहा, अपना बाज़ार व्यावसायिकता और सहयोग के लोकाचार पर काम करता है, जो इस समझौते में भी दिखाई देगा।

इस समझौते की स्थिति पर बात करते हुए श्री गांगर ने कहा कि, अपना बाज़ार के पास मुंबई में सात वितरकों, 16 सुपरमार्केट, एक पूरी बिक्री इकाई और 9फ्रेंचाइजी शॉप्स हैं। यदि खादी उत्पाद सभी आउटलेट्स में बेचे जाते हैं, तो इससे खादी के बढ़ते कारोबार तथा बिक्री में इसका शानदार प्रभाव होगा। "उन्होंने, इस वर्ष के 55,877.97 करोड़ रुपए की उत्कृष्ट बिक्री के आंकड़े भी दिए।" इस प्रकार के समझौते से बिक्री से में रोजगार सृजन और अधिक मजदूरी बढ़ाने के रूप में कारीगरों को लाभ से तिहरा लाभ होगा।

पिछले वर्ष की तुलना में, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की कुल बिक्री लगभग 90 प्रतिशत बढ़ी है। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि आज, युवा, बुजुर्ग और हर उम्र के महिलाएं खादी ले जा रही हैं।"

इसके पश्चात्, फरवरी, 2018 में अपने स्टोरों के माध्यम से शुरुआत करने के लिए अन्य खुदरा दुकानों के साथ करार करने की भी योजना बनाई गई है।

भारतीय रिटेलर्स संघ द्वारा आयोजित रिटेलर्स लीडरशिप शिखर सम्मेलन में खादी को प्राथमिकता

मुंबई में 20 फरवरी, 2018 को आयोजित रिटेल लीडरशिप शिखर सम्मेलन के भव्य समारोह को संबोधित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने वस्त्र उद्योग में 4% योगदान देने और 50 लाख नए रोजगार पैदा करने का आह्वान किया।

यह सम्मेलन -ग्राहक केन्द्रित था, जहाँ "रीडिफेनिंग वैल्यू और वैल्यूएशन" पर विचार-विमर्श के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो अंततः भारत में खुदरा उद्योग के विकास के लिए सही वातावरण बनाने के लिए एक मंच तैयार करेगा।

खादी की महिमा पर बोलते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि "खादी,- जो ईमानदारी, शुद्धता का प्रतीक है,- संस्कृति और नैतिकता और हमारे पारंपरिक कारीगरों के कौशल को प्रतिबिंबित करती है।

अध्यक्ष महोदय ने देश के प्रधान मंत्री के 'मन की बात', जिसमें उन्होंने हर मन की बात में सभी से खादी वस्त्र को उपयोग में लाने के लिए आग्रह किया है, का उद्धरण देते हुए कहा कि खादी जिसमें त्वचानुकूल वस्त्र की आवश्यकता को पूरा करने की सभी संभावनाएं हैं और यह न केवल देश में ही बल्कि वैश्विक स्तर पर भी फैशन वस्त्र के रूप में प्रचलित हुआ है।

इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि देश में खादी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने असीम क्षमता है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ और दुर्गम इलाकों

में, जहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। इस क्षेत्र में निम्नतम पूंजी निवेश अर्थात 13,500/- से रोज़गार के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं और वह भी लाभार्थियों के घर में ही रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने केवीआईसी द्वारा शुरू किये गए विभिन्न पहलों जैसे फ्रैंचाइज़ी स्टोर, खादी कॉर्नर, पोस्ट शॉपी, ई-कॉमर्स, आदि जानकारी दी। आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी के विपणन गतिविधियों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आयोग ने ग्लोबस, अपना बाज़ार, रेमण्ड जैसे स्टोर के वृहद रिटेल चेन के साथ समझौता (MoU) किया है।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा भी उपस्थित थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग और "रिटेलिंग स्टेक होल्डर" के मध्य पहल से बेहतर परिणाम होंगे और खादी को राष्ट्र के फैशन वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने में मदद मिलेगी तथा इस तरह खादी कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उनके मजदूरी में वृद्धि भी होगी।

संयुक्त सचिव द्वारा बैंकरों के साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर बैंकर्स समीक्षा बैठक 09 फरवरी, 2018 को जे.डब्ल्यू मैरियट, जुहू, मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सयुंक्त सचिव श्री बीएच अनिल कुमार ने की। इस बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के' एस. राव, श्री वाई के बारामतीकर, श्री डी. धनपाल और सभी प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में संयुक्त सचिव ने कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मंत्रालय की बहुत सफल और एक प्रमुख योजना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पीएमईजीपी के लक्ष्य में 1800.00 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और बैंकों के नोडल अधिकारियों को समयबद्ध अवधि में परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया द्रुत गति से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। योजनान्तर्गत भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजति के लिए परियोजनाओं के लक्ष्य में क्रमश:16.60 प्रतिशत और 8.60 प्रतिशत तक वृद्धि की है। पहले यह क्रमश: 12 और 7 प्रतिशत था।

बैठक में संयुक्त सचिव ने बैंकों में लंबित प्रस्तावों की मंजूरी के साथ-साथ लंबित मार्जिन मनी दावों की मंजूरी के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया और संशोधित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लक्ष्यों के साथ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग को पूरा करने का निदेश दिया।

इससे पूर्व, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा ने अग्रणी बैंक-लिंकड ऑनलाइन प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोर दिया।

निदेशक (पीएमईजीपी) श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ई-पोर्टल के लाइव डिस्प्ले और पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही बैठक में बैंकों के पास लंबित आवेदनों की स्थिति पर चर्चा की और स्वीकृत परियोजनाओं, बैंकों द्वारा मार्जिन मनी हेतु प्रस्तुत दावों, टीडीआर की स्थिति, मूल्यांकन के दौरान पाई गई कमियों की रिपोर्ट और आवेदनों के निरस्तीकरण हेतु बताये गए कारण आदि योजना से सम्बंधित वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई। एजेंडा पर विचार-विमर्श के बाद, बैठक में भावी योजना से सम्बंधित और भी कई निर्णय लिए गए।

कर्नाटक में 91वर्ष पुरानी हेरिटेज वन्दनावलु खादी संस्था का पुनरुद्धार

गांधी जी के आव्हान पर चार दलित महिलाओं द्वारा 1926 में इसे शुरू किया था।

मैसूरू, 25 फरवरी, 2018 : मैसूरु क्षेत्र के 14 से अधिक गांवों के कारीगरों के लिए यह एक सपना सच साबित होने जैसा था, जब खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 91 वर्ष पुरानी हेरिटेज वंदनावलु खादी संस्था को फिर से पुनर्जीवित कर राष्ट्र को समर्पित किया, जो 1993 में कुछ जातीय हिंसा के बाद बंद हो गयी थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) श्री जी. चंद्रमौली, जिन्होंने इस खादी संस्था का संज्ञान लिया। 1926 में इस क्षेत्र की चार दलित महिलाओं द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा किये गए आव्हान पर आत्मनिर्भरता हेतु खादी को अपनाने के लिए एक वाहक के रूप में इसे शुरू किया था। संयोग से, उन दलित महिलाओं के दृढ़ संकल्प ने गांधीजी का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने 1927 में केंद्र का दौरा किया और केंद्र में रहे। 1993 तक, 7.5 एकड़ में फैला यह परिसर जहां वंदनावलु और उसके आसपास के दर्जनों गांवों में रहने वाले लगभग 700 परिवारों के लिए रोजगार का एक अच्छा स्रोत था, जब एक घातक जातीय संघर्ष ने क्षेत्र के सामाजिक वातावरण को नष्ट कर दिया और केंद्र ने कार्य करना बंद कर दिया।

हालांकि, क्षेत्र के कुछ गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के अलावा, गांधीवादियों ने केंद्र को पुनर्जीवित करने की पुरज़ोर कोशिश की; यह अंततः लगभग 25 वर्षों तक बहरे कानों पर जूं रेंगना जैसा ही साबित हुआ। चूंकि इस सूखा पीड़ित क्षेत्र के कुशल हाथों में कोई काम नहीं था, वंदनावलु क्षेत्र विशाल सामाजिक-आर्थिक अवसाद में फंस गया।

इस केंद्र के ऐतिहासिक महत्व और कुटीर कारीगर परिवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, जोकि आजीविका का समर्थन खो चुके हैं, आयोग के अध्यक्ष ने पिछले साल पुनरोद्धार हेतु इस गांधीवादी खादी केंद्र को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने परिसर में वर्कशेड को फिर से विकसित करने में मदद की, जिसे नष्ट कर दिया गया और 100 चरखों और 20 करघों को स्थापित करने में सहायता की। श्री सक्सेना और श्री चंद्रमौली दोनों ने खादी बोर्ड की मदद से इस गैर-सरकारी संगठन को प्रोत्साहित किया जो कि पूर्व में कार्यक्रम आधारित कार्यशील पूँजी के साथ काम कर रहा था।

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि "यह सिर्फ 91 वर्ष पुरानी खादी संस्था का पुनरोद्धार ही नहीं, बल्कि यह उन चार शेर-दिल वाली दलित महिलाओं को श्रद्धांजलि है - जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान आत्मनिर्भरता के गांधीवादी साधन के साथ सामाजिक बुराइयों से लड़ने की हिम्मत की।" उन्होंने कहा, "हमने न केवल खादी गतिविधियों को, बल्कि ग्रामोद्योग गतिविधियों को भी एक सामान्य तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए बाजार इंटरफ़ेस किया है और साथ ही धीरे-धीरे समर्थन बढ़ाने की योजना भी बनायी गई है।"

उन्होंने आगे बताया कि मजदूरी की गारंटी के साथ 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार सुनिश्चित करने हेतु शहद मिशन पर प्रशिक्षण के लिए एक विस्तार केंद्र स्थापित किया गया है । "दो शौचालयों के निर्माण से परिसर में स्वच्छता की स्थिति में भी सुधार किया गया है। प्रति महिला कर्मचारी प्रति दिन 200 रुपये से अधिक की मजदूरी के साथ एक माह में 5 लाख रुपये से अधिक की क्षमता के खादी उत्पादन की शुरुआत की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि गांवों के युवाओं को रोजगार के ढांचे में लाने के लिए अधिक से अधिक ग्रामीणों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए सक्रिय रूप से रूपरेखा तैयार की जा रही है।"

आयोग मुख्यालय, मुंबई में खादी सुधार विकास कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक संपन्न

(पृष्ठ 04 से आगे...)

एमएसएमई मंत्री द्वारा केन्द्रीय मधुमक्खीपालन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान,पुणे.....

यह योजना एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्यगिकी उन्नयन में मदद करेगी।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत आवंटन 2017-18 में 1024.49 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 में 1800 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 88,000 लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करते हुए करीब 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होगें।

क्रेडिट गारंटी फंड को पहले ही 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है। इस वृद्धि और रोजगार सृजन को बडे पैमाने पर बढ़ाया जा सकेगा। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी केंद्रो की स्थापना हेतु 2017-18 में 150 करोड़ के आवंटन में साढे तीन गुना से ज्यादा वृद्धि होगी, साथ ही यह वृद्धि 2018-19 के लिए 550 करोड़ रूपए की गयी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति हब के लिए आवंटन 60 करोड़ रुपए से 9366 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और व्यापार विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा इस साल के बजट में कई अन्य घोषणाएं की गई जिसमें एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।

विविधा

कुछ 7 महीने पहले केवीआईसी द्वारा बनस डेयरी को दिए गए 650 मधुमक्खी बक्से से 3200 किलो शहद उत्पादित हुआ है। डेयरी अधिकारियों ने अहमदाबाद में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और उन्हें मधुमक्खी बक्से से प्राप्त शहद और मधुमक्खी बॉक्स की प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वाई.के. बारामतिकर के साथ डेयरी अधिकारियों भी दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्रीय केला महोत्सव-2018 में माननीय कृषि मंत्री, केरल सरकार श्री बी. एस. सुनील कुमार और संसद सदस्य, श्री सुरेश गोपी के करकमलों से डॉ. साक्षी, वैज्ञानिक केएनएचपीआई ने सर्वश्रेष्ठ अभिनव उत्पाद पुरस्कार प्राप्त किया।

केन्द्रीय ताड़ एवं ताड़ उत्पाद संस्थान, चेन्नई ने 19 फरवरी, 2018 से 23 फरवरी, 2018 तक संस्थान में बेकरी उत्पादों पर 5 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में 22 जनवरी 2018 को गुजरात खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुशाल सिंह पधीरिया और बोर्ड के अन्य अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आयोग के राज्य कार्यालय, महाराष्ट्र को प्राप्त आईएसओ प्रमाणपत्र प्रदान किया।

वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी उत्सव-2018

दिनांक 15 फरवरी ,2018 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी परिसर में राज्य स्तरीय खादी उत्सव-2018 का उद्घाटन आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना के कर-कमलो द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आयोग के माननीय सदस्य (मध्य क्षेत्र), श्री जय प्रकाश तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा एवं आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने सभी को अवगत कराया कि मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी के अन्तर्गत राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी लगाये जाने का प्रावधान था, किन्तु जगह न मिलने के कारण यहाँ राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह की प्रदर्शनी की आशा की थी, श्री बलधारी सिंह, निदेशक,वाराणसी ने उसी तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया है, इसके लिए हम उनके कार्य सराहना करते हैं। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने जो सपना देखा था कि घर-घर चरखा पहुँचे,वह सपना आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। मील का जो कपड़ा बनता है उसमें बिजली और पानी बहुत ही अधिक मात्रा में लगता है, लेकिन खादी के जो वस्त्र बनते हैं, उनमें न ही बिजली की आवश्यकता होती है और न ही पानी अधिक मात्रा में लगता है और यह खादी वस्त्र पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल हैं।

आयोग के माननीय सदस्य (मध्य क्षेत्र), श्री जय प्रकाश तोमर ने लोगों को अवगत कराया कि हमारा पहला उद्देश्य- ग्रामीणों व्यक्तियों को खादी से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है, साथ ही साथ ग्रामीण पलायन को भी रोकना है। हमारा मुख्य उद्देश्य - "जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट" उत्पाद तैयार करना है, तभी हम खादी का पूर्णरूप से विकास कर पायेंगे।

आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रीता वर्मा ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि जब मैं पिछली बार मण्डलीय कार्यालय,वाराणसी के दौरे पर आयी थी तो देखा कि जगह न मिलने के कारण प्रदर्शनी लगने पर संशय था, लेकिन निदेशक, वाराणसी के प्रयासों से ही आज यहाँ पर यह प्रदर्शनी लगी है और बहुत ही सुन्दर ढंग से

(शेष पृष्ठ 20 पर...)

राजकोट में कारीगर सम्मेलन

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने राजकोट में आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देसाई और के.प्र.पत्र समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री मनूभाई मेहता की उपस्थिति में कारीगर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

कुण्डला तालुका ग्राम सेवा मंडल, सावरकुंडला, जरी रेशम खादी ग्रामोद्योग संघ, सूरत और खादी ग्रामोदय संघ, राजकोट- तीनों खादी संस्थाओं के 40 साल पूरे होने पर (1978-2018) राजकोट में इन संस्थानों का एक खादी कारीगर एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, पूर्व अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देसाई और के.प्र.पत्र समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री मनूभाई मेहता के अलावा राज्य के निदेशक, गुजरात श्री एस. जी. हेडाऊ, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी और संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित लगभग 500 लोग मौजूद थे।

(पृष्ठ 19 से आगे...)

लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ऐसे वस्त्रों को बनाना है जो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकें और इस आधुनिक युग में लोगों की पहली पसन्द बनें।

आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मध्य क्षेत्र) श्री एस. पी. सिंह ने अपने स्वागत सम्बोधन में मंचासीन अधिकारियों का अभिनन्दन करते हुए संक्षेप में मध्य क्षेत्र की उपलब्धियों से अवगत कराया कि पिछले 02 वर्षों में मध्य क्षेत्र में 101 नयी संस्थाएँ बनायी गयी हैं, जिनसे गाँवों में 10,000 नये रोजगार सृजित हुए। खादी सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य क्षेत्र की 88 खादी संस्थाओं और 02 ग्रामोद्योगी संस्थाओं का चयन, सेवापुरी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के सहयोग से कार्यरत 475 चरखे एवं हनी मिशन के तहत लगे 150 मधुमक्खी बाक्सेज लगाने और अन्य खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों पकी जानकारी प्रदान की।

अन्त में श्री संदीप सिंह, मंत्री, कृषक खादी ग्रामोद्योग संस्थान, वाराणसी ने समारोह में भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद दिया।

बहु उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलोर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कई कदम उठाये गए हैं जिसमें ब्यूटीशियन और सिलाई पाठ्यक्रम, उद्यमिता विकास केंद्र, मोमबत्ती निर्माण और हस्तनिर्मित पेपर सेंटर आदि- चलाए जा रहे हैं, हाल ही में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र का दौरा कर केंद्र के गतिविधियों की समीक्षा की तथा केंद्र के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

त्रिवेंद्रम में पीपुल्स एजुकेशन कार्यक्रम

त्रिवेन्द्रम में अवनिसरी ग्राम पंचायत के सहयोग से पीपुल्स एजुकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग के माननीय सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) श्री जी. चंद्रमौली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर उन्होंने, केवीआईसी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्राम पंचायत के वित्तीय समर्थन के साथ खादी ग्राम परियोजना को लागू करने हेतु ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ माननीय सदस्य ने हर संभव सहायता प्रदान करने आश्वासन दिया।

खादी भवन, मैसूर का उद्घाटन

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 25/02/2018 को खादी भवन, मैसूर (खादी ग्रामोद्योग संघ, अन्नपूर्णा की एक इकाई) का उद्घाटन किया।

सदस्य(उत्तरी क्षेत्र) द्वारा प्र.मं.रो.सृ. कार्यक्रम की समीक्षा

आयोग की सदस्य(उत्तरी क्षेत्र), डा. हिना भट्ट, ने 31.01.2018 से 02.02.2018 तक अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान चण्डीगढ़ में प्र.मं.रो.सृ.कार्यक्रम की समीक्षा की।

अपने दौरे के दौरान उन्होंने मोहाली स्थित खालसा कालेज फार टेक्नोलॉजी एण्ड मेनजेमेंट में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित लोक शिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि प्रत्येक तकनीकी संस्थानों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि युवाओं को खादी और ग्रामोद्योगी योजनाओं की जानकारी दी जा सके, जिससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इस अवसर पर उन्होंने निबन्ध लेखन व डिबेट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किये।

तदोपरान्त, सदस्य महोदया ने केन्द्रशासित राज्य अतिथि गृह, सेक्टर 6, चण्डीगढ़ में पंजाब, हरियाणा और केन्द्रशासित चण्डीगढ़ में कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया और कहा कि बैंकों द्वारा राज्य स्तर से सभी वित्तीय बैंक शाखाओं को लम्बित प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके के निपटाने के लिये हिदायतें जारी की जानी चाहिये, जिसकी प्रतिलिपि उद्योग विभाग और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भी भेजी जाये। निदेशक, उद्योग व कामर्स, पंजाब सरकार ने कहा कि यदि चार प्रस्ताव प्रति माह प्रत्येक वित्तीय बैंक शाखा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत कर देती है तो वर्ष 2017-18 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में श्री डी.पी.एस.खरबन्दा, आई.ए.एस. निदेशक, उद्योग एण्ड कामर्स, पंजाब सरकार, संयोजक, एस एल बी सी, पंजाब, हरियाणा और केन्द्रशासित चण्डीगढ़, राज्य मण्डलों के सदस्य सचिव, प्रतिनिधि आर.बी.आई., उद्योग विभाग पंजाब, हरियाणा और केन्द्रशासित चण्डीगढ़ के प्रतिनिधि और श्री वी.के. नागर, राज्य निदेशक, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ के अतिरिक्त आयोग के अन्य अधिकारी- गण और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

इसके बाद उन्होंने हरियाणा तथा पंजाब की खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि सभी खादी संस्थाओं को खादी का उत्पादन बढ़ाने और कारीगरों की आय बढ़ाने के सभी प्रयास करने चाहिये। खादी कारीगरों की स्वास्थ्य जांच हेतु मेडिकल चेक अप कैम्प लगाने चाहिये। इस अवसर पर उन्होंने संस्था प्रतिनिधियों से खादी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और आश्वस्त किया कि इन्हें दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

डॉ. हिना भट ने चंडीगढ़ के पास गांव मालोवा का दौरा किया और खनिज आधारित उद्योग के तहत आयोग के राज्य कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित पारंपरिक कुम्हारी कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

जम्मू में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर समीक्षा बैठक

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सदस्य (उत्तर क्षेत्र) डॉ. हिना भट्ट ने जम्मू क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की और कार्यान्वयी एजेंसियों और बैंकों को साथ में काम करने के लिए कहा।

जम्मू डिवीजन में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 19/02/2018 को आयोग की सदस्य (उत्तर क्षेत्र) डॉ. हिना भट्ट के अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक, जम्मू-कश्मीर, उद्योग और वाणिज्य विभाग, श्रीनगर के संयुक्त निदेशक, एसएलबीसी, जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि, आरएसटीआई के निदेशक और आयोग के कश्मीर क्षेत्र के सहायक निदेशक प्रभारी श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रमुख जिला प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला अधिकारी, आरएसटीआई के निदेशक, जम्मू क्षेत्र के जिला समन्वयक खा.ग्रा.आ./ खा.ग्रा.बोर्ड के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

डॉ. हिना ने सभी प्रायोजित एजेंसियों जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोज़गार के अवसरों का सृजन करने हेतु यह योजना एक प्रभावी साधन है।

"यह बेरोजगारी से निपटने, ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों की भूमिका निभाने के लिए एक प्रभावी योजना है।"

उन्होंने बैंकों से कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही मायने में काम करने और मार्जिन मनी के वितरण में तेजी लाने के लिए कहा।

डॉ. हिना ने आशा व्यक्त की कि विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों, राज्य अधिकारियों और अन्य लाभार्थियों समेत सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान हुई चर्चाएं संपार्श्विक मुक्त ऋण(कोलटरल), समय पर बैंक स्वीकृति, मार्जिन मनी उपादान जारी करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगी और ऋण की किश्त, क्रेडिट गारंटी योजना का कवरेज, सामाजिक वर्ग अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं आदि के लक्ष्यों की जानकारी उपलब्ध होगी।

(शेष पृष्ठ 24 पर...)

(पृष्ठ 23 से आगे...)

यह बैठक सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करेगी और जम्मू क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का बेहतर कार्यान्वयन होगा, जिससे समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई और आ रहे समस्याओं की भी जांच की गई।

पूर्व में, सहायक निदेशक श्री अनिल कुमार शर्मा ने बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष (एनजेड) और सभी उपस्थितों के समक्ष वर्ष 2017-18 हेतु प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जिला-वार और बैंक-वार प्रगति के बारे में अवगत कराया ।

HMPI के तहत घरेलू एवं निर्यात विपणन पर कार्यशाला

आयोग के गांधी दर्शन, राज घाट, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में हस्तनिर्मित पेपर उद्योग के तहत घरेलू और निर्यात विपणन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सदस्य (उत्तरी क्षेत्र) डॉ हिना शफी भट्ट द्वारा किया गया।

कश्मीर में दक्षता विकास प्रशिक्षण

उद्यमों की स्थापना करने के उद्देश्य से विस्तार निदेशालय द्वारा श्रीनगर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान और एसकेयूएएसटी-के ("शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय") के सहयोग से 17.02.2018 को विश्वविद्यालय परिसर, शालीमार, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 22 बेरोजगार महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सदस्य (उत्तर क्षेत्र), डॉ. हिना भट ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और हनी मिशन के बारे में बताया कि इन योजनाओं में बेरोजगारों के लिए रोजगार की बहुत व्यापक संभावनाएं हैं और प्रशिक्षणार्थिओं को भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 200 विक्री केन्द्रों के माध्यम से उचित बाजार उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है।

1000 मधुमक्खी बक्से एवं अन्य उपकरणों का वितरण

17 फरवरी, 2018: आयोग के राज्य कार्यालय, रांची ने झारखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से उद्योग भवन, रतु रोड, रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में 1000 मधुमक्खी बक्सों और अन्य उपकरणों को वितरित किया।

इस अवसर का मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास एवं अन्य गणमान्य अतिथि के रूप में आयोग के विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण विकास)श्री अशोक भगत, झारखंड खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजय सेठ उपस्थित थे।

आयोग के इस कार्यक्रम का उद्देश्य -आधुनिक मधुमक्खी पालन को लोकप्रिय बनाकर अत्यंत दूरस्त ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिति के उत्थान हेतु मधुमक्खी पालन उद्योग को विकसित करना है।

कोल्हापुर में कुम्हारी प्रशिक्षण कार्यशाला

सिद्धिगिरि महासंस्थान, कनेरी, कोल्हापुर में आयोग के राज्य कार्यालय, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित कारीगर मेला में 11 फरवरी, 2018 को कुम्हारी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में आयोग की माननीय विशेषज्ञ सदस्य (एचआरडी), श्रीमती शीला राय और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई. के. बारामतीकर ने भाग लेकर लोगों को आयोग के उद्देशों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

थोरडी, गुजरात में गांधी मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन

11 फरवरी 2018 को थोरडी, गुजरात में तीन दिवसीय गांधी मेला -प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। श्री रेवाजी भाई, श्री कांती भाई जैसे गांधीवादियों ने अपने संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी।

इस अवसर पर आयोग के राज्य निदेशक, गुजरात श्री संजय हेडाऊ ने गांधीवादी सिद्धांत और स्वच्छता मिशन का पालन करने का आग्रह किया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण सौर चरखा था, जिसका यहां जीवंत प्रदर्शन किया गया था।

पी.एम.ई.जी.पी. योजना को धन्यवाद:

समाज की मुख्यधारा में ट्रांसजेन्डर शामिल

समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ट्रांसजेन्डरों को जागरूकता कार्यक्रम को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल करने से उन्हें सम्मानित जीवन जीने में मदद मिलेगी। आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई द्वारा सीपीपीआई, चेन्नई के माध्यम से विशेष रूप से ट्रांसजेन्डरों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 26 ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया। 6 ट्रांसजेंडरों ने ताड़ पत्ते से उत्पाद बनाने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना तहत ऋण के लिए आवेदन किया है। डीएलटीएफसी के समक्ष यह मामला उठाया गया और डीएलटीएफसी ने सभी 6 ट्रांसजेन्डरों के ऋण आवेदन को मंजूरी दी। दृढ़ विश्वास के बाद, बैंक ने सभी छः ट्रांसजेंडरों के लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान की। आवश्यकता के अनुसार 6 ट्रांसजेंडरों ने आरएसटीआईआई में अपना उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का लक्ष्य पूरा किया और उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किया गया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी की गई। उन्हें जल्द ही स्वीकृत ऋण जारी किया जायेगा और आगे की कारवाई को बाद में सूचित किया जाएगा।

आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत उपर्युक्त उपलब्धि समाज के हाशिए पर आने वाले वर्ग के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन है। हमारे निरंतर प्रयासों से आयोग ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से अधिक ट्रांसजेंडरों का नामांकन करने की योजना बनाई है।

आयोग के राज्य निदेशक, गुजरात श्री संजय हेडाऊ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार श्री पूनम चंद परमार से मुलाक़ात की। जहाँ 28 जनवरी 2018 को गांधीनगर में खादी विकास पर चर्चा की गई।

आरसेटी के राज्य निदेशकों और बैंकरों की समीक्षा बैठक

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और झारखंड राज्य के अभ्यारण्य कार्यक्रम के तहत राज्य निदेशक आरसेटी और बैंकरों की समीक्षा बैठक 26 फरवरी, 2018 को आरोग्य भवन, विकास भारती, बर्यातु, रांची में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के माननीय विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण विकास) पदमश्री अशोक भगत ने की तथा बैठक में आयोग के निदेशक (पीएमईजीपी), मुंबई, आयोग के राज्य निदेशक, रांची, राज्य निदेशक (आरएसटीआई), निदेशक (आरएसईटीआई) एवं आयोग के राज्य कार्यालय, रांची के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में आयोग के विशेषज्ञ सदस्य (आरडी), पदमश्री अशोक भगत ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि सचिव (वित्त) ने बैंकों के संबंधित नियंत्रण प्रमुखों के साथ लंबित आवेदनों पर आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है। उन्होंने विशेष रूप से एससी/एसटी आवेदकों के लिए अलग से डीएलटीएफसी आयोजित करने की सलाह दी है।

विचार विमर्श के दौरान, निदेशक (पीएमईजीपी) श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर ने आरएसईटीआई निदेशकों के पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों के आवेदनों को अपलोड करने के लिए जिलावार लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 दिन और 10 दिन का ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही सभी के लिए 10 दिनों में परिवर्तित हो जाएगा। जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इसके बाद, निदेशक (पीएमईजीपी) ने अभ्यारण्य की अवधारणा के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने 2008-09 से 2016-17 की अवधि के 4464 मामलों के लिए एससी/एसटी के बैकलॉग पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा, सभी जागरूकता शिविरों को कवर करने के लिए संभावित पीएमईजीपी लाभार्थियों के आवेदन उत्पन्न करने हेतु राज्य सरकार, एनजीओ और ट्राइफेड, आरएसटीआई, डीआईसी के समन्वय में आयोग के राज्य कार्यालय, झारखंड द्वारा इन शिविरों को आयोजित किया जाएगा और एनजीओ या सरकारी संगठनों के माध्यम से पीएमईजीपी लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया गया कि ईडीपी प्रशिक्षण

(शेष पृष्ठ 29 पर...)

केन्द्रीय बजट 2018

एमएसएमई मंत्रालय के लिए आम बजट के प्रावधान की मुख्य बातें

आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके। इस क्षेत्र (सेक्टर) के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2017-18 के 6481.96 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 6552.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं (सीजीटीएमएसई के अलावा) के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 3680 करोड़ रुपये से 59 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 5852.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 506 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 1006 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह योजना एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन में मदद करेगी।

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवंटन को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 1024.49 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि गैर-कृषि क्षेत्र में लगभग 88,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

- साख गारंटी कोष को पहले ही 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ-साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधारों की बदौलत इस सेक्टर में ऋण वृद्धि और रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 150 करोड़ रुपये से तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- खादी अनुदान के तहत आवंटन को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 265.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 415 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गैर-परंपरागत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सोलर चरखा मिशन की एक नई योजना भी प्रस्तावित की गई है, ताकि और ज्यादा रोजगारों का सृजन हो सके।

- परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (एसएफयूआरटीआई) के तहत बजटीय आवंटन को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर

(शेष पृष्ठ 29 पर...)

(पृष्ठ 28 से आगे...)

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 125 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे परंपरागत एवं ग्रामीण उद्योगों में रोजगार सृजन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

- 'एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना)' के तहत आवंटन को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में 232 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य 100 आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना है। इससे उद्यमिता और रोजगार सृजन में तेजी आएगी।
- राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के तहत आवंटन को 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 93.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि एससी/एसटी उद्यमियों के कारोबार में वृद्धि को नई गति प्रदान की जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी घटकों हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समग्र आवंटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

आरसेटी के राज्य निदेशकों और बैंकरों की समीक्षा बैठक.....

(पृष्ठ 27 से आगे ...)

पूरा करने के बाद सभी एसडीआर, आरएसटीआई पोर्टल पर ईडीपी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे , इसके बाद, एक एसएमएस अलर्ट लाभार्थियों को आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा और संबंधित बैंकरों को इसके लिए स्वचालित रूप से ई-मेल भेजा जाएगा।

इससे पहले, आयोग के राज्य निदेशक, रांची ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

चर्चा के दौरान राज्य निदेशक आरसेटी , झारखंड और आरसेटी के अन्य जिला निदेशकों ने पीएमईजीपी दिशानिर्देशों के मुताबिक काम करने और तदनुसार आवेदन अपलोड करने का आश्वासन दिया।

एसएलबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, रांची के प्रतिनिधि ने बताया कि वे पीएमईजीपी के तहत लंबित आवेदनों को विशेष अभियान के तहत 15 दिनों के भीतर जल्दी निपटान कर रहे हैं। अन्य बैंकरों को भी इसी प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी ताकि वे आवेदन की सुस्त वितरण प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर सकें।

आयोग के राज्य निदेशक, झारखंड ने बताया कि 10 ऐसी कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 6 विकास भारती, बिशनपुर और 4 राज्य कार्यालय, रांची के माध्यम से संपन्न हुई हैं , जिसमें 800 आवेदकों की पहचान की गई है, जो एक सप्ताह के भीतर अपने आवेदन अपलोड करेंगे।

बैठक, राज्य निदेशक आरसेटी, झारखंड श्री आनन्दी लाल के धन्यवाद के साथ संपन्न हुई।

पीएनबी आरसेटी, रावरी द्वारा पीएमईजीपी के तहत एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित

पीएनबी आरसेटी, रावरी ने 19 फरवरी 2014 से 28 फरवरी 2018 तक पीएमईजीपी के तहत एक ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम के दौरान पीएनबी आरसेटी, रावरी द्वारा पीएमईजीपी के तहत आयोजित एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सम्भावी 16 लाभार्थियों / उद्यमियों ने भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण के अंतिम दिन डीसीओ, मुख्य प्रबंधक पीएनबी और निदेशक,पीएनबी, आरसेटीआई ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किये।

एक स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुसार

"खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में 100 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल किए"

वर्ष 2008-09 में, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा आवंटित कुल सब्सिडी का 50 प्रतिशत से कम उपयोग में लाया गया, वर्ष 2016-17 में - यह 100 प्रतिशत अंक, अर्थात 100.37 प्रतिशत पार कर गया । इस सफलता का श्रेय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को जाता है, जो पीएमईजीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है ।

विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2016-17 में पीएमईजीपी के लिए 1,100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 15 मार्च को ही इसे हासिल किया । तत्पश्चात, मंत्रालय ने लक्ष्य में 100 करोड़ रुपये और जोड़ा, जोकि 25 मार्च को प्राप्त किया गया था । पुनः इसमें 50 करोड़ रुपये जोड़े गए थे, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की समग्र उपलब्धि भी 2016-17 में 1,281 करोड़ रुपये के वार्षिक आंकड़े के साथ पार कर गई। इतना ही नहीं, लगभग 4 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ, वित्त वर्ष 2015-16 में अनुमानित परियोजना लागत 4,800 करोड़ रुपये के साथ लगभग 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुरुग्राम द्वारा किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन में यह देखा गया । पूरे देश में स्थित 10044 पीएमईजीपी इकाइयों (कुल इकाइयों का पांच प्रतिशत) और लाभार्थियों, हितधारकों और बाह्य स्रोतों से आंकड़ें एकत्रित करने के पश्चात् इनकी प्रत्यक्ष जांच की गई, इसके बाद, मूल्यांकन अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार प्रति परियोजना औसत रोजगार 7.66 व्यक्ति साथ में इकाई में रोजगार का सृजन करने हेतु औसत लागत 94,855 रुपये है और प्रति प्रोजेक्ट औसत लागत 7,26,760 रुपये है । "रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ।" यूनिट रोजगार सृजन करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम लागत 2,65,412 रुपए (नागालैंड) और 25,070 (तमिलनाडु) में रूपए थे।"

एमडीआई का अध्ययन आगे बताता है कि लाभार्थियों की औसत आयु 36.8 साल थी और उनमें से 42.39 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के थे, इसके आलावा 5.8 प्रतिशत अल्पसंख्यकों और 10 प्रतिशत महिलाएं थी | "उत्पादन और सेवाओं में क्रमशः 53 प्रतिशत और 45 प्रतिशत लाभार्थी शामिल थे, बैंकों द्वारा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में क्रमश: 46 प्रतिशत और ऊपर 54 प्रतिशत दर्ज किया गया था।"

इकाइयों के संबंध में – इकाई कार्य निष्पादन और गैर-लाभदायक संपत्ति (एनपीए) में सक्षम नहीं, एमडीआई रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से देखा है कि यूनिट की स्वीकृति करते समय यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर से उचित व्यवहार्यता या विश्लेषण का अभाव हो सकता है । काफी हद तक, एनपीए के प्रमुख कारक हितधारकों और लाभार्थियों को अलग करना है , लाभार्थियों में इकाई चलाने या स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं के ज्ञान की कमी है । इन पहलुओं में पहली पीढ़ी के उद्यमियों को इस तरह की समस्याएं जैसे 'उत्पाद गुणवत्ता का महत्व' और कुशल जनशक्ति इत्यादि शामिल हैं। "

उत्पादों के खपत (उपभोग करने के सम्बन्ध में) के संदर्भ में, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकांश लाभार्थियों (79.53 प्रतिशत) ने बताया कि उनके उत्पादों / सेवाओं का घरेलू उपयोग केवल 9.56 प्रतिशत ग्रामीण लाभार्थियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि शहरी लाभार्थियों द्वारा यह 5.84 प्रतिशत किया जाता है। रिपोर्ट में आगे कहा कि "बहुसंख्यक लाभार्थियों (75.07 प्रतिशत) ने बताया कि उनके इकाइयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है"।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पीएमईजीपी योजनाओं के सभी चार उद्देश्यों और सम्मान की शर्तों के 14 अंकों को ध्यान में रखने के लिए अध्ययन की पद्धति तैयार की गई थी। सभी राज्यों में, डीएलटीएफसी बैठकों की संख्या तीन-तिमाही के तीन निर्दिष्ट मूल्य से कम थी। जब कि उत्तर अंचल में, डीएलटीएफसी की सबसे अधिक संख्या चंडीगढ़ में थी, अर्थात 1.15, पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में क्रमशः झारखंड (1.05) और असम (0.7) थे।

अधिकतर मामलों में, बैंक द्वारा सिफारिश की गई आवेदनों को निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर ऋण स्वीकृत नहीं प्रदान की गई अर्थात ऋण प्रदान करने में अधिक विलम्ब हुआ। अतः यह पाया गया कि सेवा क्षेत्र के मुकाबले उत्पादन क्षेत्र के लिए ऋण की मंजूरी देने में अधिक विलम्ब किया गया। जबकि उत्तर अंचल में, संपत्ति के हाईपोथिकेटेड मूल्य से अधिक के लिए कोलटरल सुरक्षा की राज्य से कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, पूर्वी अंचल में, केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेटेड मूल्य के अधिक कोलटरल सुरक्षा के लिए रिपोर्ट की थी। इसी तरह, पूर्वोत्तर और दक्षिण अंचल में, मेघालय / मिजोरम और आंध्रप्रदेश / केरल ने परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेटेड मूल्य से अधिक की तुलना में कोलटरल सुरक्षा की सूचना दी थी। जबकि पश्चिम अंचल में, संपत्ति के हाईपोथिकेटेड मूल्य के ऊपर कोलटरल सुरक्षा के लिए कोई भी राज्य से सूचना नहीं दी गई थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि यहां तक कि केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सफलता दर को लेकर संज्ञान लिया गया था। "2018-19 के बजट में हमने 1,800 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जब कि विगत वर्ष 2017-18 में 1,024 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जोकि 78 फीसदी विकास दर है। चूंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खादी से काफी प्रभावित हैं, क्योंकि वे इसे देश के आर्थिक परिवर्तन का एक साधन मानते हैं, इसलिए हम उनके विजन का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में पश्चिमी क्षेत्र की समीक्षा बैठक संपन्न

आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना; उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई.के. बारामतीकर; राज्य निदेशक, अहमदाबाद और मुंबई श्री संजय हेडाऊ; राज्य निदेशक, केवीआईसी नागपुर श्री राहुल गजभिये; राज्य निदेशक, केवीआईसी, गोवा श्री एस. ताम्बे; गुजरात खादी बोर्ड के सचिव,श्री टेलर, सदस्य श्री डी. के. दशा, उद्योग भारती, गोंडल के सचिव श्री चंद्र पटेल ने पश्चिम क्षेत्र की आंचलिक समिति की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

समीक्षा बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य कार्यालय, केवीआईसी, मुंबई के अधिकारियों को क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : विशेष.....

हर वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन, जिन महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ता से समाज में समय-समय पर अपना योगदान दिया है, ऐसी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। जागृति में हम ऐसी दो महिलाओं की सफलता की कहानी प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिन्होंने आयोग के सहयोग से अपने कर्तव्यों और कार्यों से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनायी है।

1. वह जिन्होंने अपनी शर्तों पर सफलता प्राप्त की:-

ऐनी स्वीनी ने कहा है कि "अपनी शर्तों पर सफलता को परिभाषित करें, अपने नियमों से इसे प्राप्त करें, और एक जीवन का निर्माण करें जिसे आप जीवन जीने पर गर्व महसूस करते हैं।" हस्तनिर्मित साबुन नीव हर्बल की प्रोपराइटर श्रीमती शिखा जैन इसका एक जीवंत उदाहरण है। आरईसी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक, भौतिकवाद की प्रमुख विश्वव्यापी शिखा जैन ने अपना जीवन जीने के लिए एक नए विजन की खोज करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आकर्षक कैरियर को अलविदा कहा।

उन्होंने अपने इंजीनियर पति के मदद से नीव नामक हर्बल साबुन का निर्माण करने के लिए श्री अनुराग जैन और शिखा जैन द्वारा (नई शिक्षा और पर्यावरण विजन) नीव ट्रस्ट की स्थापना की गई। 2006 में उन्होंने नीव ट्रस्ट की स्थापना करने का विजन बनाया जो "स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने, पर्यावरण सम्बंधित जागरूकता फैलाने और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त करके इसके द्वारा न्यायसंगत विकास की तलाश करना" की अवधारणा पर आधारित है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए 'नीव साबुन' - पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार है इसके लिए 2007 में खादी ग्रामोद्योग आयोग की आरईजीपी योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं का नाम पंजीकृत किया गया।

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से 31 अगस्त 2010 को भारत के पूर्व क्षेत्र में स्थित उत्कृष्ट आरईजीपी इकाई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, जिसके लिए उनके पास समय भी नहीं था।

'नीव' के सम्बन्ध में :-

'नीव हर्बल हस्तनिर्मित साबुन' विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट-गुणवत्ता वाले, सभी प्राकृतिक कॉस्मेटिक उत्पादों का उत्पादन करता है जिसमें बालों के तेल से लेकर शैंपू और साबुन तक सभी वस्तुएं शामिल हैं। इन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किसी भी कृत्रिम अथवा

रासायनिक अवयवों या रंगों को उपयोग में लाए बगैर शीत भण्डारण प्रक्रिया को उपयोग में लाया जाता है।

वर्ष 2007 में, पति और पत्नी अनुराग और शिखा जैन ने एक संगठन की स्थापना की, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थायी तरीके से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समर्पित इस संगठन से उम्मीद की गई है।

भारत के झारखंड के ग्राम हर्लंग में स्थित "नीव इकाई" गांव समुदाय में रहने वाली महिलाओं के लिए श्रम

का एक सम्माननीय स्रोत प्रदान करती है। इन महिलाओं के हाथों से उत्पादित उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों को उपयोग में लाते हैं, जैसे एलोवेरा, गुलाब, तुलसी, मेहंदी, हिबिस्कस,भृंगराज, ब्राह्मी, अश्वगंधा और शतावरी इत्यादि 'नीव युनिट' के नजदीक ही खेत में उत्पादित प्राकृतिक पौधों को उपयोग में लाया जाता है और इसे सीधे ही उपादक और किसानों से खरीदा जाता है। इस उत्पादित तेल में महुआ तेल भी शामिल है- झारखंड के स्वदेशी वृक्ष से निकाले गए इस तेल को - पारंपरिक रूप से त्वचा का देखभाल करने के लिए आदिवासियों द्वारा उपयोग में लाया जाता था।

इस इकाई में दस स्थायी महिला कर्मचारी और 30 ग्रामीण महिला वेतन अर्जक हैं। ग्रामीण लड़कियों ने यूनिट में अपनी कमाई के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस साबुन इकाई में प्रवेश करने के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य है। नीव साबुन इकाई में पूर्व में कार्यरत्त 3 महिला कार्यकर्ताओं ने अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर दिया है और 5 महिलाओं ने टेल्को में स्थायी नौकरियां प्राप्त की हैं। नीव द्वारा प्रशिक्षित स्व-सहायता समूह की 200 ग्रामीण महिलाओं द्वारा साबुन निर्माण, पैकेजिंग और तरल साबुन बनाने में मदद की गई है।

नीव हर्बल हस्तनिर्मित साबुन को एक्सएलआरआई के छात्रों द्वारा सामाजिक उद्यमिता में केस स्टडी के रूप में लिया गया है। केस स्टडी का चयन स्टर्न स्कूल ऑफ बिज़नेस, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में किया गया था। 2014 में, नीव साबुन केस स्टडीज-इंटरनेशनल ओआईकोस केस राइटिंग प्रतियोगिता के सामाजिक उद्यमिता ट्रैक में उपविजेता बन गया।

अप्रैल 2010 में आईआईटीएफ, केंटन आयात निर्यात मेला, चीन सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों, दक्षिण अफ्रीका-एशिया शिखर सम्मेलन 2011 अदीस अबाबा में, यूरोप का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला - 2012 में, मिला इटली में आर्टिगिओनो फेयर में भाग लिया। इकाई द्वारा हर्बल उत्पादों का उत्पादन, बिक्री और विपणन में 200 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही बिक्री और ग्राहक डेटा बनाए रखने के लिए कंप्यूटर पर काम करने के लिए कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

भारत के सभी प्रमुख शहरों में 200 प्रमुख रिटेल बिक्री केन्द्रों में 'नीव' उत्पाद साबुन उपलब्ध हैं, जिन्होंने आईटीएल लेब, दिल्ली से साबुन के आयुर्वेदिक और

प्रयोगशाला प्रमाणन एवं भारत सरकार के ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत कॉस्मेटिक लाइसेंस प्राप्त किया है।

उनके उत्पाद रेंज में 130 विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे हस्तनिर्मित साबुन, बॉडी वाश, हेंड वाश, शैंपू, तेल, फेश पैक, क्रीम, मसाज ऑयल, लोशन, स्क्रब, काजल, डिफ्यूज़र आदि शामिल हैं।

सलम्स (slums) में परियोजनाएं :-

नीव' ने पिछले तीन वर्षों से 'एक एकीकृत सलम डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम' का कार्यान्वयन किया है जो जमशेदपुर स्थित बर्मामाइंस के 6 बस्तियों के आसपास स्थित है। इन मुख्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास और जीवनरक्षक जनरेशन शामिल हैं । इसने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के समर्थन से 5 सलम महिलाओं के समूह के साथ 'एक हस्तनिर्मित पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट' की शुरूआत की, जो तस्करी के शिकार हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित परियोजनाएं :-

महिला स्व-सहायता समूह – 'नीव' ने 15 स्व - सहायता समूहों का गठन किया और उन्हें बैंक से लिंक किया गया। महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है जैसे सिलाई, टोकरी की बुनाई और साबुन बनाने इत्यादि।

स्कॉलरशिप कार्यक्रम –

'नीव' - 60 प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में सहायता कर रहा है।

राइस ईंटेंसिफिकेशन सिस्टम –

'नीव'-नाबार्ड द्वारा समर्थित एक परियोजना के तहत अपने खेतों में एसआरआई को कार्यान्वित करने के लिए 650 किसानों को सुविधा दे रहा है।

किसान क्लब –

'नीव'- नाबार्ड के समर्थन के साथ 15 किसान क्लब बनाने की सुविधा दे रहा है।

जल सर्वेक्षण –

'नीव' ने झारखंड के चार जिलों में जल संसाधनों और उनके उपयोग को मैप करने के लिए एक सर्वेक्षण किया।

पारंपरिक बीज सर्वेक्षण –

'नीव' ने पारंपरिक बीज के उपयोग के अध्ययन के लिए झारखंड के 2 जिलों के 100 किसानों से मुलाकात की है।

माइक्रो (लघु) स्वास्थ्य बीमा योजना :

'नीव' ने गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जमशेदपुर में अपोलो डीकेवी की "माइक्रो स्वास्थ्य बीमा योजना" लागू की ।

स्वास्थ्य शिविर :-

नीव' - स्थानीय सीबीओ के समन्वय से नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है, जहां ग्रामीणों को टाटा अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों द्वारा नि: शुल्क दवाइयाँ और मुफ्त उपचार दिया जाता है।

रिसाइकिल्ड्स क्विल्ट्स प्रोजेक्ट:

'नीव' ने पुराने कपड़ों को रजाई या गद्दों में बदलने के लिए 15 कारीगरों को रोजगार दिया । 2008 में सर्दियों में राहत के लिए बिहार के बाढ़ पीड़ितों हेतु 1000 ऐसी रजाईयां भेजी गई थी।

पुरस्कार :-

- पति अनुराग जैन के साथ, जनवरी 2009 में "झारखंड युवा चेतना सम्मान" प्राप्त किया।
- 2010 में भारत के पूर्व क्षेत्र में स्थित खादी और

ग्रामोद्योग आयोग की महत्वपूर्ण आरईजीपी इकाई 'नीव हर्बल हस्तनिर्मित साबुन' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

- पति अनुराग जैन के साथ, जनवरी 2011 में "झारखंड युवा चेतना सम्मान" प्राप्त किया।
- 2012 में झारखंड में, केवीआईसी की उत्कृष्ट यूनिट होने के लिए 'नीव हर्बल हस्तनिर्मित साबुन' के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त किया।
- शिक्षा श्रेणी में - वर्ष की 'महिला'-महिला पुरस्कार के लिए नामांकित किया।

रुचि के क्षेत्र :-

नीव ने महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, वंचितों के लिए शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक और स्थायी उद्यमिता, आध्यात्मिक ज्ञान और लेखन इत्यादि क्षेत्र में रूचि दिखाई है।

सामाजिक उत्तरदायित्व :-

'नीव हर्बल हस्तनिर्मित साबुन' भारत में सबसे ज्यादा पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों जैसे महिला सशक्तीकरण, स्थायी उत्पादन और वंचितों के लिए शिक्षा जैसे कुछ लोगों का समर्थन करने के लिए लाभ हेतु उपयोग में लाया जाता है। जब आप 'नीव' उत्पाद खरीदते हैं, तो आप न सिर्फ एक पर्यावरण-अनुकूल बन रहें हैं और सभी-प्राकृतिक कॉस्मेटिक उत्पाद उपयोग में ला रहें है, बल्कि इन कारणों का समर्थन भी कर रहें हैं और 'नीव यूनिट' के बेहतर कल के लिए काम कर कर रहें हैं|

हर्लंग गांव में नीव विद्यालय :-

'नीव चैरिटेबल ट्रस्ट' द्वारा समर्थित सामाजिक मुद्दों में से ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा एक मुद्दा है। 'नीव विद्यालय' गांव में 200 रुपये प्रति माह में अंग्रेजी माध्यम में उच्च गुणवत्ता वाली इंटीग्रल शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल के दर्शन(फिलोसोफी) को '5 एस' द्वारा समझाया जा सकता है। '5 एस' सिद्धांत एक व्यक्ति की चेतना के विकास के आरोही क्रम में कहा गया है। इसका अर्थ है (1) सदाचार – स्व-अनुशासन (2) स्वाध्याय – स्वज्ञान /स्व-अध्ययन (3) स्वावलंबन - आत्म निर्भरता 4. स्वराज्य - स्वशासन, 5 सामराज - आत्मज्ञान / ग्लोबल माइंड । वेदांतिक भाषा में ब्रह्म या संपूर्ण ब्रह्माण्ड को दर्शाया जाता है। आत्म-मंथन मानव चेतना की परिपूर्णता है जिसमें एक व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है - और यह दोनों स्पष्ट और अनभिज्ञ है।

2.सूखे फूलों की सुगंध:

सूखे फूलों के शिल्प कार्य (डीएफसी) यानि "प्रेस्सेड ड्राई फ्लावर क्राफ्ट" (पीडीएफसी) में पूरी दुनिया के लिए अपने आप में पहली भारतीय मास्टर शिल्पकार और औरोआर्ट्स की प्रमुख एवं औरोआर्ट्स सोसाइटी के अध्यक्ष-श्रीमती अनुराधा साहू जो ग्लोबल वार्मिंग और हरित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वैश्विक चिंतन के लिए एक अभिनव अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट की स्थापना के लिए मजबूती से संघर्षरत हैं ।

प्राचीन काल से, फूलों का प्रतीकवाद दुनिया भर में संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फूलों के लिए प्यार एक प्राकृतिक वृत्ति है, फूल प्रकृति के उपहारों में से एक हैं तथा भारतीय फूल भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हैं और वे भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य हिस्सा भी हैं। वर्तमान हस्तशिल्प के साथ प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता के नैतिक सिद्धांतों को एक बार फिर से जोड़कर, प्रेस्ड सूखे फूलों के शिल्प के रूप में एक सुंदर एकीकरण विकसित किया गया है।

किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं पर सुई से चिपकाए गए किसी भी रासायनिक / कृत्रिम रंग उपयोग में लाये बगैर

फूलों को हाथों से तोडकर स्वाभाविक रूप से सुखाया जाता है तथा किसी भी प्रकृतिक प्रक्रिया से या सुई से फूलों को जोड़ा जाता है ताकि एक अनुठी वस्तु तैयार हो सके । आईटी प्राकृतिक रूप में प्रकृति को फिर से परिभाषित करता है, यह प्रकृति प्रेरित प्राकृतिक शिल्प है। हस्तनिर्मित कागज की प्राकृतिक वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला में फूलों, पत्तियों, घास, टेंडरिल, बीज, सोल की लकड़ी, बांस और स्वदेशी प्राकृतिक संसाधनों का एक संयोजन, लकड़ी से लेमिगनेट, सिरेमिक टाइलें, वनस्पतीय पर्दे, प्राकृतिक फाइबर, सीसहेल्स, सूखी पत्ती (सूखीपत्तियां), बांस, आदि को उपयोगी हरी जैविक पर्यावरणनुकूल हाथ से तैयार की किये गए उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला पेटेंट प्राप्त (जापान, जर्मनी, अमेरिका और सिंगापुर)**
- **राष्ट्रीय पुरस्कार 2005**
- **जैविक प्रमाणित उत्पादक**

फूलों को हाथों से तोड़ कर, प्राकृतिक रूप से सूखे फूल को सूई के माध्यम से चिपकाया जाता है, इससे रोजगार का सृजन होता है जो फूलों की एक अनूठी भाषा बोलता है। यह सबसे बढ़िया धन है जो कि प्राकृतिक वनस्पति है और सबसे सस्ता भी है एंव इसे आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है तथा पर्यवारणानुकुल है, यह जैव रूपांतरित (बायो-डीग्रेडेबल) है और इससे विविध

प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह सामग्री बाजार से नहीं खरीदी जाती है बल्कि कच्ची सामग्री पर निर्भर करता है, लेकिन क्राफ्टिंग के क्षेत्र से स्थानीय वनस्पति इकट्ठा करके वस्तुएं तैयार की जाती है।

इन्हें वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2016 में स्फूर्ति योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अग्रेषित किया गया, जहां ऑरोर्टस में 200 ग्रामीण महिलाओं को टिकाऊ, उपयुक्त और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल रूप में जीवनयापन करने के लिए मदद मिलती है, जो पर्यावरण को ख़राब नहीं करते हैं और यह जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह मुद्दा ग्रामीण भारत से संबंधित है।

यह स्फूर्ति योजना, सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ में कार्यरत्त हैं, इसके माध्यम से ऐसे कृषि परिवारों को जिनके पास जमींन नहीं है उन्हें पुनर्वास की सुविधा मिलती है और सीमांत समूहों के ग्रामीण / शहरी गरीब अशिक्षित महिलाओं के क्षमता निर्माण से उन्हें स्थाई रोजगार देने हेतु क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर प्रशिक्षण, डिजाइन, तकनीकी सहायता, विकास गतिविधि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन्हें विपणन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहां कारीगर कच्चा माल नहीं खरीदता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक स्रोतों जैसे खेतों और जंगलों से प्राकृतिक वनस्पति से एकत्रित करता है।

Wooden Laminate

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....

Khadi ties up with retailers to enter shopping malls

बजट में लघु उद्योगों को दिया गया प्रोत्साहन- गिरिराज सिंह

MSME उद्योगों को अधिक महत्व-सिंह

पुणे के टेक्सटाइल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का किया दौरा

7 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर

'महाखादी मॉडेल देशात राबवावे'

मधमाशी पालन केंद्रांचा विस्तार लवकरच

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांचे प्रतिपादन

प्रतिनिधी, पुणे

महाखादीचे मॉडेल देशभर राबवावे : गिरिराज सिंह

Khadi ties up with retailers to enter shopping malls

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....

Budget has given big thrust for MSME sector: Giriraj Singh

GEETA PAWAR
PUNE, FEBRUARY 3

Union minister Giriraj Singh distributed 10 honeybee boxes to each trainee during his visit to the Central Bee Research Training Institute.

UNION MINISTER for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Giriraj Singh said the Union Budget has given a boost to the MSME sector. "The 2018-19 Budget has given a big thrust to MSME sector, to boost employment and economic growth. The Budget allocation has gone up this year from Rs 6,481.96 crore to Rs 6,552.61. Apart from the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CHTMSE), the allocation for individual schemes has gone up this year by 59 per cent, from Rs 3,680 crore to Rs 5,852.61 crore," Singh said. He was in Pune to review honey promotion activities under the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) at the Central Bee Research Training Institute.

"Under the KVIC, 800 villages will be provided employment every year. Along with hand charkhas, a new scheme of Solar Charkha Mission has also been proposed to harness non-conventional solar energy to further employment generation, which will provide 4 lakh people employment each year through KVIC," said Singh. In the Union Budget, allocation under Khadi Grant has been enhanced from Rs 265.10 crore to Rs 415 crore.

The budgetary allocation for the National Manufacturing Competitiveness Programme, which helps technology upgrading in the MSME sector, has gone up from Rs 506 crore to Rs 1,006 crore. Funding for Prime Minister Employment Generation Programme has gone up from Rs 1,034.49 crore to Rs 1,800 crore for generating self-employment opportunities through establishment of about 88,000 micro enterprises in non-farm sector, providing employment to around 7 lakh people.

Allocation for the Credit Guarantee Fund has gone up from Rs 2,500 crore to Rs 7,500 crore. There has been more than a three-fold increase in allocations for the setting up of state-of-the-art Technology Centres, from Rs 150 crore to Rs 550 crore.

Under Scheme for Fund of Regeneration of Traditional industries, the Budget has increased allocations from Rs 10 crores to Rs 125 crore, which will boost employment generation in traditional and rural industries, he said.

The budget for ASPIRE (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship) has been raised from Rs 50 crore to Rs 232 crore with an aim to set up 100 livelihood business incubators and 20 technology business incubators. The allocation for the National SC/ST Hub has been raised from Rs 60 crore to Rs 93.96 crore with a view to providing business growth for SC/ST entrepreneurs.

Another announcements which has given a boost to the MSME sector is the extension of a reduced corporate tax rate of 25 per cent, currently available for companies with a turnover of less than Rs 50 crores, to companies reporting turnover up to Rs 250 crore in the financial year 2016-17, to benefit micro, small and medium enterprises.

"Under formal employment, this year, 70 lakh people were provided with the EPF (Employees Provident Fund) number. I hope that in 2019, it will rise to 1 crore people... I hope that there will be a rise in employment opportunities in the coming year. However, the rising population is a drawback," said Singh.

कलाकारों को डेस्क, बक्स और टूल-किट्स मिलेंगे

लाइफ रिपोर्टर @ पटना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) के माध्यम से ग्राम विकास परिषद, रॉटी, मधुबनी पेंटिंग कलस्टर का शुभारंभ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने किया. उद्घाटन के पहले एसके गुप्ता, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना द्वारा मंच पर आसीन सभी अतिथियों और उद्घाटन समारोह में उपस्थित मधुबनी व अन्य जिलों से आये कलाकारों, अभिभावकों, माता एवं बहनों का स्वागत करते हुए स्फूर्ति योजना की विस्तृत जानकारी दी. तदोपरांत खष्टिनाथ झा, सचिव ग्राम विकास परिषद, रॉटी द्वारा परियोजना अंतर्गत दिये जानेवाले कार्यों व उससे मिलनेवाले लाभ के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर कार्यक्रम का क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम विकास परिषद, रॉटी चयनित है. इस योजना के तहत जिले के नौ गांवों जिवारपुर, रॉटी, हरिनगर, पिलखवाड़, अमादा, लहेरियागंज, सिमरी, सौराठ व मधुबनी के 600 कलाकारों का चयन किया गया है. इसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जायेगा. साथ ही कलाकारों को बिचौलियों से निजात दिलाने का भी सशक्त प्रयास किया जायेगा. योजना के तहत सभी कलाकारों को पेंटिंग बनाने के लिए डेस्क, बक्सा, चटाई व टूल-किट्स भी दिये जायेंगे. उद्घाटन के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यपाल जी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्वी क्षेत्र) एसएस सील, डॉ राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगीय प्रशिक्षण केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना के प्राचार्य डीके राय और आयोग के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

ई-मार्केटिंग सबसे सुलभ व ताकतवर माध्यम : गिरिराज

जासं, मधुबनी : वर्तमान समय में ई-मार्केटिंग सबसे सुलभ एवं ताकतवर माध्यम बनता जा रहा है। 2015 में यह चार हजार करोड़ का था और आज 20 हजार करोड़ का हो गया है। हम चाहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग्स को भी ई-मार्केटिंग से जोड़ कर इसका विकास किया जाए। ये बातें गुरुवार को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम विकास परिषद के रॉटी मुख्यालय में आयोजित मधुबनी पेंटिंग कलस्टर स्फूर्ति योजना के शुभारंभ के मौके पर कहीं। उन्होंने कहा कि जब तक मधुबनी पेंटिंग्स को तकनीक से नहीं जोड़ा जाएगा, इसका तेजी से विकास नहीं हो सकेगा। हमलोगों ने यह योजना इस कमी को पूरा करने के लिए ही शुरू की है। इससे रोजगार का विस्तार होगा। कहा, मिथिला में मखाना, पेंटिंग्स एवं खादी को नया रूप देकर हम हजारों रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। गिरिराज सिंह ने खादी की स्थिति को बदलने के लिए भी तकनीक की मदद लेने की वकालत की। योजना में एक साथ छह सौ महिला-पुरुष कलाकार बेसिक प्रशिक्षण के साथ डिजाइन, डेवलपमेंट कार्यक्रम, एक्सपोजर, स्पोकन इंगलिश, कंप्यूटर साक्षरता आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

600 कलाकारों का पेंटिंग के लिए चयन

पटना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से ग्राम विकास परिषद रॉटी मधुबनी की ओर से मधुबनी पेंटिंग कलस्टर का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री ने किया। स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया। पूर्व में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक एसके गुप्ता ने अतिथियों व मधुबनी तथा अन्य जिलों से आए कलाकारों, अभिभावकों का स्वागत किया। योजना के तहत जिले के नौ गांवों में 600 कलाकारों का चयन किया गया है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....

केंद्रीय सूक्ष्म-लघुउद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह यांनी शनिवारी शिवाजीनगर येथील केंद्रीय मधमाशी प्रशिक्षण केंद्राला भेट देऊन विविध योजनांचा आढावा घेतला.

मधमाशी पालन केंद्रांचा विस्तार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह यांची माहिती

'महाखादी'चे मॉडेल देशभर राबवा

गिरिराज सिंह : ग्रामोद्योगाला चालना देणाऱ्या उपक्रमाचे कौतुक

सोलर चरखा प्रकल्प

Efforts needed to control increasing population: Union Min for MSMEs

ST CORRESPONDENT

Pimpri: Union Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Giriraj Singh said here on Saturday that due to the policies of Central government over 70 lakh new jobs were created in the country. Singh added that as the opposition parties do not acknowledge the development of the country, they are encouraging caste politics in the country.

Singh was speaking after inaugurating the exhibition under vendors development programmes, which was organised by Pune Engineering Cluster at Auto Cluster auditorium in Chinchwad. Singh said that the government is continuously working for boosting the industrial sector, and there are continuous efforts for bringing transparency through digitisation. Singh said that India is growing rapidly and hence the world is watching India. He further added that in the current budget, 59 per cent of total fund allocation on the ...

... MP Amar Sable, MLA Mahesh Landge, Mayor Nitin Kalje, Leader of House in PCMC Eknath Pawar, President of Pune Engineering Cluster Sagar Shinde, President of Pimpri Chinchwad Small Industries Association Sandip Belsare, Director of MSME Development Department ... were present for the function.

सोलर चरखा योजना राबविणार

वंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म व लघु आणि मध्यम उद्योगाच्या बजेटमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत ५९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना अधिक चालना मिळणार असून, कोट्यवधी हातांना रोजगार मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडून लवकरच प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील एका गावात 'सोलर चरखा' योजना राबविली जाणार असून, ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःच्या गावात ६ ते १० हजार रुपयांचा रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच अधिकाधिक नवउद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून कर्ज मिळणार असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले.

(L-R) Anil Ganger, Chairman, Apna Bazar, Vinai Kumar Saxena, Chairman, KVIC holding the MOUs in Mumbai yesterday. S T Kajale, CEO, Apna Bazar is seen at the extreme right.

KVIC signs MOU with Apna Bazar

By Dominic Rebello

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has signed an Memorandum of Understanding (MOU) with Apna Bazar for setting up a "Khadi Korner" at Charkop and Mulund in Mumbai's suburbs targetting the middle class.

The MOU was signed by representatives of Apna Bazar and KVIC in the presence of KVIC Chairman Vinai Kumar Saxena, and Apna Bazar's Chairman, Anil Ganger and CEO, S T Kajale. "The tie-up is expected to generate tremendous impact in escalating khadi sales through Apna Bazar, which has seven distributors, 16 supermarkets, one wholesale unit and nine franchise outlets in Mumbai, said Kajale.

"Our focus is to establish 'Khadi Korners' in major retail showrooms and malls. We recently had excellent high-level interaction in this regard with CEOs of major retail chains," said Vinai Kumar Saxena, Chairman, KVIC. Cotton Bazar, Future Group are soon expected to tie up with KVIC. We are expecting sales to rise between 5-6%, he added.

Kangana to don Khadi in on silverscreen in Manikarnika

Actress Kangana Ranaut will don khadi outfits in her upcoming film 'Manikarnika: The Queen of Jhansi'. KVIC said the attire of the lead cast of the movie is being sponsored by it. "It is official now - after dressing up officials in several government offices, Khadi is now making its way to silverscreen! Kangana Ranaut, in her lead role in 'Manikarnika: The Queen of Jhansi'," KVIC said.

Sponsored by Khadi and Village Industries Commission (KVIC), the costume line for the film shall be designed by ace designer Neeta Lulla. Lulla has already picked up fabric costing around Rs 25 lakh from KVIC.

"Our sales were Rs. 2007 cr last year and we are expecting sales of around Rs 3,000 crore this financial year," said Saxena. "We have witnessed a growth of 30-40% in sales in Noida, which shows khadi's acceptability and are expecting the same figure nationally, as khadi product prices range between Rs 50 to Rs 3,000 per sq metre," he said.

Khadi gets prominence in the Retailers Leadership Summit organized by Retailers Association of India

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....

खादी ग्रामोद्योग का अपना बाजार से समझौता

मुंबई. खादी ग्रामोद्योग ने अपना बाजार से समझौता किया है। खादी को घर घर तक पहुंचाने के लिए यह समझौता किया गया है। इस दौरान केवीआईसी के विनाई कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी के सभी अच्छे प्रकार के कपड़े अपना बाजार के माध्यम से बेचे जाएंगे। खादी के कपड़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया है। खादी के कपड़े नेता और बुजुर्ग लोगों में ज्यादा लोकप्रिय है। अब इसे आम जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। इस समझौते में अपना बाजार के सीईओ एमटी कजीले का भी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से खादी का व्यवसाय बढ़ेगा। देशभर में खादी का व्यवसाय ५५८७९ करोड़ का है। जिसे इस समझौते के माध्यम से बढ़ाया जाएगा।

Khadi gets prominence in the Retailers Leadership Summit

Addressing the prestigious event of Retail Leadership Summit organized yesterday in Mumbai by the Retailers Association of India, **Vinai Kumar Saxena, Chairman, KVIC, vowed to contribute 4% in textile industry and generate 50 lakh new employment.**

Reiterating on the glory of Khadi "Khadi which is symbol of sincerity, purity and honesty, reflects the culture and the ethos and the skill of our traditional artisans. Speaking on this occasion he said that Khadi sector has a great potential for creating employment opportunities in the country especially in the rural areas and remote and inaccessible areas. It can generate employment with a low capital investment as low as Rs. 13,500/- and that too providing employment at the door step of the beneficiary.

Khadi for Kangy's queen

Manikarnika makers collaborate with government-run Khadi Commission for Ranaut's Rani Laxmibai costumes

SONIL DEDHIA
sonil.dedhia@mid-day.com

WHILE ensuring Rani Laxmibai's bravado spills onto screen when Kangana Ranaut portrays the historical character in Manikarnika: The Queen Of Jhansi, the makers are also ensuring that her personality and passion find a voice on screen. So that the costumes reflect the wave of patriotism that had swept the country, the team has collaborated with the government-run Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to procure hand-spun organic fabric for the star's wardrobe.

A source tells mid-day, "Rani Laxmibai was among the leading warriors of India's freedom struggle. She would head to the battlefield dressed as a man, donning clothes made of khadi. In a bid to ensure that the character looks authentic, the makers requested costume designer Neeta Lulla to make ensembles using the fabric."

The last leg of shooting is underway in Rajasthan. Producer Kamal Jain says that Lulla will be designing the costumes for Ranaut and the rest of the cast involved in the sequence. "We want to stay true to history. In December, we discussed the costumes for this final schedule with Neeta, and chose to approach the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to procure the fabric. Neeta has designed amazing pieces, ones that have never been seen before. We also plan to showcase the costumes at an event in the coming months as part of the film' promotions."

Talking about the nitty gritties of creating the attires, a source associated with the costume department says, "Rani Laxmibai was seen in clothes that the traditional Maratha men wore at the time of war. Various colours have been used to design the costumes."

Vinai Kumar Saxena, chairman, KVIC, says, "We are proud of this association. Rani Laxmibai had waged the first war of Independence, wearing khadi. Celebrated or not, khadi has had a tryst with Indian history."

Republic @republic

Here's why 'Khadi' is Kangana Ranaut's choice

Kangana Ranaut to don Khadi on silverscreen in Manikarnika - Republic World
republicworld.com

6:12 PM - 21 Feb 18

6 Retweets **20** Likes

Khadi India

अपने शहर के एक
खादी इण्डिया
आउटलेट पर जाएं,
गर्व से खरीदें उच्च गुणवत्ता के
हस्तनिर्मित वस्त्र और उत्पाद,
जो आपके
देशवासियों द्वारा
ग्रामीण भारत में बनाये गए हैं !

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाईट : www.kvic.org.in

नजदीकी खादी आउटलेट की जानकारी के लिए
मोबाईल ऑप डाउनलोड करें।

Follow us on kvicindia @kvicindia

भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृद्धि बुनते है

KVIC ARTWING 2016